

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग लगा नंबर दो पर पहुंचा यूपी

पिछले साल थी 12वीं रैंकिंग, तेजी से बढ़ती **कारोबार सुधार** कार्ययोजना की नीति

जगरण खरो, नई दिल्ली : देश में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। केंद्र सरकार की तरफ से कारोबार सुधार कार्ययोजना लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश को वर्ष 2019 के लिए दूसरा स्थान दिया गया है। एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था। वैसे आंध्र प्रदेश ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि तेलंगाना दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को चौथा और झारखंड को पांचवां स्थान मिला है। जबकि हिमाचल प्रदेश को सातवां और उत्तराखंड को 11वां स्थान मिला है। वर्ष 2015 के मुकाबले हिमाचल और उत्तराखंड ने अपनी रैंकिंग में क्रमशः 10 व 12 स्थानों का सुधार किया है। दिल्ली भी इस दौरान 23 से 12वें स्थान पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ छठे, हरियाणा 16वें स्थान पर है। जम्मू व कश्मीर 21वें स्थान पर और बिहार 26वें स्थान पर रखा गया है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने की दिशा में इस तरह की रैंकिंग का विशेष महत्व है। अब जबकि जापान व



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल कार्यक्रम में रैंकिंग की घोषणा की • पेट

सफलता

- आंध्र पहले स्थान पर बरकरार, मध्य चौथे व झारखंड पांचवें स्थान पर
- हिमाचल की रैंकिंग 10, उत्तराखंड की रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार

12 वें स्थान पर था उत्तर प्रदेश 2018 के लिए जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में

कुछ राज्यों ने आर्थिक सुधारों को सुनियोजित तरीके से लागू करने और उन्हें जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन विशिष्ट रहा है।

निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री

राज्यों की तरफ से उद्योग जगत के लिए माहौल में जितना सुधार किया जाएगा, देश के लिए निवेश जुटाना उतना ही आसान होगा। पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री

वर्ष 2025 तक बनेंगे पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नई दिल्ली: पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर में 24 फीसद की गिरावट के बावजूद सरकार यह मान रही है कि वर्ष 2025 तक 5 देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, "अगर हम मिल कर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दें तो वर्ष 2025 से पहले ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाई जा सकती है।" सनद रहे कि पिछले वर्ष भारतीय इकोनॉमी की साइज 2.82 ट्रिलियन डॉलर रही थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसमें 10 से 15 फीसद गिरावट की बात कही जा रही है।

विश्व बैंक की मदद से बनती है रैंकिंग

यह रैंकिंग केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से करनी शुरू की है। इसमें राज्य सरकारों की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट, भ्रम कानून, पर्यावरण संबंधी पंजीयन, सूचना व भूमि की उपलब्धता व सिंगल विंडो को मानक बनाया गया है।

आस्ट्रेलिया के साथ मिल कर भारत ने चीन के मुकाबले एक विश्वस्तरीय व विश्वस्तरीय सप्लाई चेन बनाने की

मुख्यमंत्री योगी के दावे पर आंकड़ों की मुहर

निवेशकों व उद्यमियों के बीच उत्तर प्रदेश की छवि बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय रहे। प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग सुधार करने के लिए 186 कदम उठाए थे, जिन्हें बहुत कारगर माना गया है। प्रदेश सरकार के दावे पर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने भी मुहर लगा दी। उप ने 2017-18 की तुलना में दस पायदान की ऊंची छलांग के पीछे बहुत अहम भूमिका सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की है। देखें >> 2

कॉशिश शुरू की है तो इसका फायदा ईज ऑफ डूइंग के मामले में बेहतर करने वाले राज्यों का होगा। यह

रैंकिंग हर वर्ष मार्च में जारी की जाती है लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई है।